(ङ) 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय तथा अन्य सहायता या सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) 1987 और 1988 के दौरान उन्हें सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित भावी लक्ष्य क्या-क्या हैं?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत अथवा इससे अधिक रही, उनके नामों का विवरण-पत्र संलग्न है **[देखिये** परिशिष्ट CXLIII, उपाबन्ध सं० 93]

(ख) प्रश्न के भाग (क) के सन्दर्भ में दिए गए विवरण पत्र में, जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के नाम नहीं है उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है। उन राज्यों ने लक्ष्यों को पूरा न करने के कई कारण बताए हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं :--

-भूमि अधिग्रहण, जिसमें वन्य भूमि शामिल है, सम्बन्धी मुश्किलें।

-निधि का अभाव

-निर्माण सामग्री का अभाव

-दूसरी बार सहायता आदि देने के लिए पुराने लाभग्राहियों की जानकारी लेने में मुश्किलें।

(ग) और (घ) मासिक प्रगति रिपोर्ट, जो निकृष्ट निष्पादन वाले सूत्रों/मदों को दर्शाती है, के जारी होने के बाद मुख्य सचिवों/मुख्य मंत्रियों को समय-समय पर पत्र भेजे जाते हैं जिन के द्वारा उनका ध्यान उन सूत्रों/मदों की ओर दिलाया जाता है जिनके अन्तर्गत उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन निकृष्ट रहा हो और उन्हें उन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उचित उपाय करने का आग्रह किया जाता है।

(ङ) और (च) 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए विशेष रूप से और अलग से कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। इनको राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के संगत योजना शीर्षों से लिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लि राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है परन्तु सम्पूर्ण योजना के लिए खंड ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों का दिखाया जाना

2136. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों को दिखाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस योजना को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) से (ग) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश भर में फैली 257 यूनिटों के अपने संजाल के साथ चलते फिरते वाहनों के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन करता रहा है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं।

दिल्ली में 2 केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं जो संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली इसके ग्रामीण क्षेत्रों सहित में फिल्में दिखाती हैं।